

SHRI N. C. KASLIWAL: May I know whether in these four States the Government consider the desirability of having mobile units especially to cater to the needs of the people residing in the villages?

DR. SUSHILA NAYAR: Sir, the treatment of trachoma is a very simple thing. What it means is application of a particular ointment for five days in the week, one week in a month, to be repeated for six months. The State of Gujarat has done a magnificent job by organising this programme practically through the efforts of voluntary workers. We have supplied them with the ointment, we have also supplied them with some vehicles, but they are not employing full-time staff for this purpose. Some of the other States wanted some more staff, and according to the pattern worked out with the help of the W.H.O. and UNICEF we have allowed them a certain number of units. Sir, we want to see what will be the result of the voluntary effort as against the effort where we have given full time units and then we shall see how this programme should be taken to the rest of the country.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: The hon. Minister has just said that the treatment of trachoma is going on in four States. May I know whether the hon. Minister has got the number of cases treated in those States, what has been the result, and how many of them have cured?

DR. SUSHILA NAYAR: The treatment is in progress all over the country, in all the States, in all the districts. The regular dispensaries, hospitals, doctors, they give the treatment. In these four States a comprehensive trachoma control programme is being attempted. The number of patients treated, I am afraid, I cannot tell now.

*39. [Withdrawn.]

दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

*४०. श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' :
क्या निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में अब तक कुल कितनी झुग्गियां और झोपड़ियां गिराई जा चुकी हैं ;

(ख) जो झुग्गियां और झोपड़ियां गिराई गई हैं उनके एवज में झुग्गी वालों को कितने प्लॉट दिये जा चुके हैं और वे प्लॉट कितने कितने गज के हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उन्हें सिर्फ २५ वर्ग गज जमीन किराये पर देने का हल में निश्चय किया है ?

t [DEMOLITION OF JHUGGIES IN DELHI

*40. SHRI P. L. KUREEL *URF* TALIB: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of jhuggies and Jhonparies demolished so far in Delhi and New Delhi;

(b) the number of plots given to jhuggi-owners in lieu of the demolished jhuggies and jhonparies and the size of each plot in yards;

(c) whether it is a fact that Government have recently decided to give them only 25 square yardi of land on rent?]

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० एल० नस्कर) :
(क) और (ख) जून, १९६१ से जुलाई, १९६३ तक लगभग ७८०० झुग्गियां गिराई गईं, जिनमें से ७१८२ परिवारों को १६३ मकान, ३६५२ अस्ती वर्ग गज वाले प्लॉट और ३३६७ पच्चीस वर्ग गज वाले

प्लाट झुग्गियों और झोंपड़ियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत दिये गये ।

(ग) इस योजना में ५००० मकानों, अस्सी वर्ग गज वाले २०,००० विकसित प्लाटों और २५ वर्ग गज वाले २५,००० डेरा डालने के प्लाटों (कैम्पिंग प्लाट्स) की व्याख्या की जानी है ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND REHABILITATION (SHRI P. S. NASKAR): (a) and (b) Between June 1961 and July 1963, about 7800 jhuggies were demolished, out of which 7182 families were allotted 163 tenements, 3652 plots of 80 square yards and 3367 plots of 25 square yards under the Jhuggies and Jhonparies Removal Scheme.

(c) The Scheme contemplates the provision of 5000 tenements, 20,000 developed plots of 80 square yards each and 25,000 camping plots of 25 square yards each]

श्री प्यारे लाल कुरील ददपालब :
 क्या माननीय मंत्री जी को - معلوم है कि
 ये जो २५ स्कवायर यार्ड्स के प्लाट हैं
 वे इतने छोटे हैं कि झुग्गी वाले जिनके
 घर में ५ या १० मेम्बर्स होते हैं उनकी इन
 प्लाटों में कब्र भी नहीं बन सकती है रहना
 तो दूर रहा । तो क्या इस तरह से गवर्नमेंट
 स्लम्स को और डवलप करेगी ?]

†[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' :
 क्या माननीय मंत्री जी को मालम है कि
 यह जो २५ स्कवायर यार्ड्स के प्लाट
 हैं वह इतने छोटे हैं कि झुग्गी वाले जिनके
 घर में ५ या १० मेम्बर्स होते हैं उनकी इन

प्लाट में कब्र भी नहीं बन सकती है रहना
 तो दूर रहा । तो क्या इस तरह से गवर्नमेंट
 स्लम्स को और डवलप करेगी ?]

श्री मेहर चन्द खन्ना : माननीय
 सदस्य ने शायद समझा नहीं । जहां तक
 रहने का ताल्लुक है उसके लिये ६० मुरब्बा
 गज के प्लाट्स होंगे, लेकिन जहां तक
 कैम्पिंग साइट का ताल्लुक है उसके लिये
 प्लाट्स सिर्फ २५ मुरब्बा गज के होंगे ।
 मौजूदा झुग्गी और झोंपड़ियों में जितनी
 जमीन होती है उससे ज्यादा जमीन इन
 प्लाट्स में है, कम नहीं है ।

श्री प्यारे लाल कुरील ददपालब :

क्या यह जो २५ स्कवायर यार्ड्स के प्लाट
 हैं उनको टम्पोरेरी कैम्प बनाने के लिए
 सरकार उनको कोई लोन देगी । या
 वह खुद उनको बनायेंगे ?]

†[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' :
 क्या यह जो २५ स्कवायर यार्ड्स के प्लाट
 हैं उनको टम्पोरेरी कैम्प बनाने के लिए
 सरकार उनको कोई लोन देगी । या
 वह खुद उनको बनायेंगे ?]

श्री मेहर चन्द खन्ना : जैसे पहले
 उन्होंने अपनी झुग्गी और झोंपड़ियां बनाई
 हैं, वैसे ही अब भी बना लें । न पहले वे
 कुछ देते थे और न अब गवर्नमेंट कुछ ले
 रही है ।

श्री प्यारे लाल कुरील ददपालब :

अब न कब्रों को तोड़ा गया और न
 भूमि नक्सान हो-। अल्टीमेट अब वह कहाँ से
 इतना पैसे लायेंगे कि वे खुद ज़ोनिंग
 बनायें ?]

†[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' : उनकी झुगियों को तोड़ा गया और उनका बहुत नुकसान हुआ। इसलिये अब वह कहां से इतना पैसा लायेंगे कि वह खुद झोंपड़ियां बना लें।]

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह इन्जाम हमारे ऊपर लगाना सरीहन नाजायज है। दिल्ली में पचास-साठ हजार झुग्गी झोंपड़ियां हैं और उनमें न कोई सफाई का इन्तजाम है और न कोई पढ़ाई का इन्तजाम है। दस बारह करोड़ रुपये लगा कर उनको बसाने की योजना बनाई गई है। यह एक अच्छा और नेक काम है और इसमें सब को मदद करनी चाहिये।

شروی پھارے لال کوریل دہطالبہ :

یہاں جھکی اور جھونپڑی والوں کی تعداد لاکھوں ہے - اس لئے چند ہزار پلاٹ دیئے سے یہ پرابلم حل نہیں ہوگی۔ جو ۸۰ اسکوائر یارکس کے پلاٹس ہیں ان پر مکان بنانے کے لئے سرکار ان کو کوئی لون یا گرانٹ دیکھی یا نہیں؟

†[श्री प्यारे लाल कुरील "तालिब" : यहां झुग्गी और झोंपड़ी वालों की तादाद लाखों है। इसलिये चन्द हजार प्लाट देने से यह प्रब्लम हल नहीं होगी। यह जो ८० स्क्वायर यार्ड्स के प्लाट्स हैं उन पर मकान बनाने के लिए सरकार उनको कोई लोन या ग्रान्ट देगी या नहीं?]

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमने झुग्गी झोंपड़ियों का बाकायदा दिल्ली में सेंसस लिया है और सेंसस के वक्त जो १९६० में मौजूद थीं उनको हमने सिलिप दी है और उनकी तादाद ५० हजार के करीब है।

अब अगर दिल्ली में हर रोज झोंपड़ियां बढ़ती रहीं तो यह प्रब्लम कभी साल्व नहीं हो सकती।

SHRI B. K. GAIKWAD: May I know what was the urgency in demolishing the huts of the poor Scheduled Caste people in these rainy days, Tiow far they have been thrown out, and what arrangement has been made for *the hutment dwellers there?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: The reasons are simply humanitarian. We have to tackle the problem of their rehabilitation, and I have taken them to proper sites and I shall see that they are properly rehabilitated.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: May I know whether the hon. Minister has seen in the local press the report that while the jhuggies were being demolished, the people who have been demolishing these jhuggies have also destroyed their belongings?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: Sir, three or four operations have taken place recently, and what we do is that we send trucks, we see that the families are properly removed, we see that they are taken "to proper site". Unfortunately the jhuggies have to be demolished, otherwise there is further squatting or resquatting.

شروی پھارے لال کوریل دہطالبہ :

کہا مانڈیہ ملٹری جی یہ پٹائیں کے کہ جو ۸۰ مربع فٹ کے پلاٹس ہیں یہ اٹھیز کے نام رجسٹر کئے جائیں گے اور ان کو مالک کا حق دیا جائے گا؟

†[श्री प्यारे लाल कूरोल " (तालिब) ": क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो ८० मुरब्बा गज के प्लॉट्स हैं यह अलाटीज के नाम रजिस्टर किये जायेंगे और उनको मालिक का हक दिया जायेगा ?]

श्री भेरूचन्द खन्ना : जो पैसा देगा वह मालिक बनेगा और जो पैसा नहीं देगा वह किरायेदार रहेगा । यह तो हो नहीं सकता कि सौ-मचास रुपये गज की जमीन मुफ्त दे दी जाय । अगर इस तरह से देना शुरू किया तो भगवान के नाम पर कोई जमीन दिल्ली में नहीं रहेगी ।

REMITTANCE ABROAD OF EARNINGS FROM FOREIGN FILMS

*41. SHRI A. D. MANI: Will the Minister of INTERNATIONAL TRADE be pleased to state the arrangements under which earnings from foreign movie films are allowed to be remitted abroad?

THE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE (SHRI MANUBHAI SHAH): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Imports of Cinematograph films exposed are mainly effected under arrangements made with the Motion Pictures Export Association of America and the Rank Film Distributors of India Ltd., who are allowed imports on a 55 per cent, quota basis. Remittances from net remittable earnings are limited to Rs. 10 lakhs per half year in the case of the former and Rs. 50,000 per half year in the case of the latter. The rest of the net earnings is held under blocked accounts in India subject to withdrawal for certain permissive usages like developing export of Indian films in non-traditional markets and production of films in India, with the approval of the Government of India.

SHRI A. D. MANI: I have seen the statement, and I would like the Min-

ister to explain the import of this sentence: "Imports of Cinematograph films exposed are mainly effected under arrangements made with the Motion Pictures Export Association of America and the Rank Film Distributors of India Ltd., who are allowed imports on a 55 per cent, quota basis". I understand that the practice in the film distribution trade is for some producers to insist on 80 per cent, of the net earnings fixed to be sent back to their countries. Does this quota refer to that or to some other matter?

SHRI MANUBHAI SHAH: No, Sir. It is not that. When the foreign exchange trouble started, we could not afford to import foreign films because of the foreign exchange situation. So, we entered into an agreement with Hollywood, the Motion Pictures Export Association of America, and the British film industry, because these are the only two English speaking countries from which we import films, and therefore we fixed the quota at 55 per cent. But the remittance which I have mentioned there is much less, not more than Rs. 10 lakhs per half year in the case of the United States and Rs. 50,000 per half year in the case of the Rank Film.

SHRI A. D. MANI: I understand further that some of the Indian distributors of these foreign films are allowed to export films from India to other Asiatic countries but that under the arrangements which they have with the foreign producers, the net foreign exchange earnings from those countries are not credited to their Indian account but to their foreign account. This has been mentioned by the Employees Union in a statement made to the Bonus Commissioner. Has the attention of the Government been drawn to that aspect?

SHRI MANUBHAI SHAH: This is a very great menace and we are trying to tackle it because, when the films are exported, they go on the net worth, and all the exhibition charges,